झारखंड उच्च न्यायालय रांची

आपराधिक अपील (खंडपीठ) सं. **1961/2023**

विमल कुमार पासवान उर्फ विमल पासवान, आयु- लगभग 27 वर्ष, पिता- बादल पासवान,

गाँव- अपरमंद्रा, बारोरा, डाकघर- नवाडीह, थाना- बारोरा, जिला- धनबाद

याचिकाकर्ता

बनाम

झारखंड राज्य

विरोधी पक्ष

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायण प्रसाद
माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव

याचिकाकर्ता के लिए: श्री गौतम कुमार, अधिवक्ता

श्री संदीप कुमार बर्नवाल, अधिवक्ता

सुश्री सविता कुमारी, अधिवक्ता

राज्य के लिएः सुश्री लिली सहाय, सहायक लोक अभियोजक

03 दिनांक **09.01.2024** :

न्यायमूर्ति श्री सुजीत नारायण प्रसाद के अनुसार

1. वर्तमान अपील राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी अधिनियम, 2008 (जिसे आगे अधिनियम 2008 के रूप में संदर्भित किया जाएगा) की धारा 21(4) के तहत दायर की गई है, जो 31.05.2023 के आदेश के खिलाफ है जो माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-II, धनबाद द्वारा पूर्व-गिरफ्तारी जमानत याचिका संख्या 1072 वर्ष 2023 में पारित किया गया है, जो बारोरा पी.एस. केस संख्या 10 वर्ष 2022 से संबंधित है, जिसमें आर्म्स अधिनियम की धाराएँ 25(1-बी)(ए)/26/35 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/4 के तहत अपराध के लिए पंजीकृत किया गया है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की पूर्व-गिरफ्तारी जमानत की प्रार्थना को अस्वीकृत कर दिया गया है।

2. वर्तमान मामले को 'आदेशों के लिए' शीर्षक के तहत सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें कार्यालय नोट है कि मामला समय सीमा द्वारा बाधित है क्योंकि इसे अधिकतम वैधानिक अवधि 90 दिन के बाद दायर किया गया है।

3. इस प्रकार की कमी को इंगित करने का कारण यह है कि अधिनियम 2008 की धारा 21(5) में ऐसा प्रावधान है जो धारा 21(4) के तहत दायर अपील करने की समय सीमा प्रदान करता है, जिसके अनुसार अपील दायर करने की आवश्यकता अधिकतम अवधि 90 दिन है।

4. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने उक्त कार्यालय नोट का विरोध किया है।

5. यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि याचिकाकर्ता के अनुसार भी, अधिनियम 2008 की धारा 21(5) लागू नहीं होती, बल्कि, समय सीमा अधिनियम की धारा 5 लागू होगी। लेकिन, समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के लागू होने के समर्थन में देरी को माफ करने के लिए कोई अंतर्वर्ती याचिका दायर नहीं की गई है।

6. इसके अलावा, उपरोक्त कार्यालय आपत्ति को चुनौती देने के लिए कोई हलफनामा भी दायर नहीं किया गया है। लेकिन, चूंकि उक्त कार्यालय नोट का विरोध किया गया है, इसलिए न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह उक्त आपत्ति का निपटारा करे।

7. याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अधिनियम 2008 की धारा 21(5) को अनिवार्य नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह निर्देशात्मक/अनिवार्य है, क्योंकि धारा 21(5) के पहले उपबंध में 'may' शब्द डाला गया है, जो अपीलीय न्यायालय, अर्थात् उच्च न्यायालय को 90 दिनों की अवधि से अधिक देरी को माफ करने का अधिकार प्रदान करता है।

8. उनके तर्क के अनुसार भी, देरी माफ करने के लिए याचिका दायर करने की आवश्यकता है लेकिन कोई अंतर्वर्ती याचिका दायर नहीं की गई, जबकि यह ज्ञात था कि अपील 90 दिनों की देरी के बाद दायर की गई है।

9. सुश्री लिली सहाय, अधिवक्ता (ए.पी.पी.) जो प्रतिवादी-राज्य की ओर से उपस्थित हैं, ने उपरोक्त प्रस्तुतिकरण पर गंभीर आपत्ति जताई है और अधिनियम 2008 की धारा 21(5) के दूसरे उपबंध का सहारा लिया है, जिसे विशेष प्रावधानों के संदर्भ में निर्देशात्मक नहीं कहा जा सकता।

10. इस न्यायालय ने पक्षों के लिए उपस्थित अधिवक्ताओं की सुनवाई की है और उनके द्वारा प्रस्तुत तर्कों की सराहना की है।

11. यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि यह न्यायालय अधिनियम 2008 की धारा 21(4) के तहत दायर अपील की सुनवाई कर रहा है, जो माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व-गिरफ्तारी जमानत के लिए प्रार्थना को अस्वीकृत करने वाले आदेश के खिलाफ है, जो "निर्धारित अपराधों" से संबंधित है।

12. यहाँ प्रश्न यह है कि कार्यालय नोट का विरोध करते हुए यह इंगित किया गया है कि अपील भी 90 दिनों की अवधि के बाद दायर की जानी चाहिए, क्योंकि धारा 21(5) को अनिवार्य नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह निर्देशात्मक है।

13. लेकिन यहाँ प्रश्न यह होगा:

"क्या अपीलीय न्यायालय के पास याचिकाकर्ता की ओर से मांगी जा रही वैधानिक अनिवार्यता की व्याख्या करने का अधिकार है?"

14. कानून स्पष्ट रूप से स्थापित है कि अपीलीय न्यायालय के पास कानून की व्याख्या करने का अधिकार नहीं होता, बल्कि अपीलीय न्यायालय को वैधानिक अनिवार्यता के अनुसार सख्ती से आगे बढ़ना चाहिए, इस सिद्धांत पर कि जब कोई अधिनियम यह निर्धारित करता है कि कोई विशेष कार्य किया जाना चाहिए, तो इसे निर्धारित तरीके से किया जाना चाहिए और किसी अन्य तरीके से नहीं। इस संबंध में उत्तर प्रदेश बनाम सिंहारा सिंह और अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है, [एआइआर (1964) एससी 358], जिसमें पैरा 8 में निम्नलिखित निर्णय दिया गया है:

> "... इसका परिणाम यह है कि यदि किसी कानून ने कोई कार्य करने की शक्ति प्रदान की है और उस विधि को निर्धारित किया है जिसमें उस शक्ति का प्रयोग किया जाना है, तो यह अनिवार्य रूप से 14 अधिनियम को निर्धारित किए गए तरीके के अलावा किसी अन्य तरीके से करने से रोकता है। नियम के पीछे का सिद्धांत यह है कि यदि ऐसा नहीं होता, तो वैधानिक प्रावधान भी लागू नहीं किया गया होता.....।"

15. इसी प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बाबू वेरघीज़ और अन्य बनाम बार काउंसिल ऑफ केरल और अन्य, [(1999) 3 SCC 422] में, पैरा 31 और 32 में निम्नलिखित निर्णय दिया:

> *"31. यह कानून का एक मौलिक सिद्धांत है जो लंबे समय से स्थापित है कि यदि किसी विशेष कार्य को करने का तरीका किसी अधिनियम के तहत निर्धारित किया गया है, तो वह कार्य उसी तरीके से किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं। इस नियम की उत्पत्ति टेलर*

बनाम टेलर के निर्णय से की जा सकती है, जिसे नज़ीर अहमद बनाम किंग एम्परर में लॉर्ड रोच द्वारा अनुसरण किया गया था, जिन्होंने कहा था: "[डब्लू]जहाँ किसी निश्चित तरीके से एक निश्चित कार्य करने का अधिकार दिया गया है, वह कार्य उसी तरीके से किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं।

32. यह नियम तब से इस न्यायालय द्वारा राव शिव बहादुर सिंह बनाम राज्य उत्तर प्रदेश और फिर दीप चंद बनाम राज्य राजस्थान में स्वीकृत किया गया है। इन मामलों पर इस न्यायालय के तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा राज्य उत्तर प्रदेश बनाम सिंहारा सिंह में विचार किया गया और नज़ीर अहमद मामले में स्थापित नियम को फिर से मान्यता दी गई। यह नियम तब से न्यायालयों द्वारा अधिकार क्षेत्र के प्रयोग पर लागू किया गया है और इसे प्रशासनिक कानून के वैधानिक सिद्धांत के रूप में भी मान्यता दी गई है।"

16. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आयकर आयुक्त, मुंबई बनाम अंजुम एम.एच. घासवाला और अन्य, [(2002) 1 एससीसी 633] में, पैरा 27 में निम्नलिखित निर्णय दिया:

"..... यह विचार करने का सामान्य नियम है कि जब कोई अधिनियम किसी प्राधिकरण को किसी विशेष तरीके से कार्य करने का अधिकार देता है, तो उस प्राधिकरण को इसे केवल उसी तरीके से करना चाहिए जो अधिनियम में निर्धारित किया गया है।"

17. इसके अलावा, यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि सांविधिक प्रावधान में निहित प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ है और कोई भी शब्द निरर्थक नहीं कहा जा सकता। इस संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एफ़ाली फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1989) 4 एससीसी 378 के मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है।

"39. ------- किसी भी अधिनियम के किसी भी भाग को अनावश्यक या अतिरिक्त नहीं माना जाना चाहिए। अधिनियम में प्रत्येक शब्द को एक अर्थ दिया जाना चाहिए। ऐसा निर्माण जो अधिनियम की भाषा के किसी भी भाग को प्रभावहीन छोड़ दे, सामान्यतः अस्वीकृत किया जाएगा। अधिनियम के प्रत्येक खंड को संदर्भ और अधिनियम के अन्य खंडों के संदर्भ में इस प्रकार व्याख्यायित किया जाना चाहिए कि पूरे अधिनियम का, यथासंभव, एक सुसंगत निर्माण किया जा सके।"

18. उपरोक्त निर्णय का संदर्भ देने का कारण यह है कि अपीलीय न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न तो सांविधिक प्रावधान को कम करके पढ़ने के अधिकार का प्रयोग कर रहा है और न

ही सांविधिक प्रावधान को असंवैधानिक/अवैध घोषित करने का, क्योंकि यह अधिकार अपीलीय न्यायालय के पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए अपीलीय न्यायालय को सांविधिक आदेश के अनुसार आगे बढ़ना आवश्यक है।

19. प्रश्न जो उठाया गया है कि उपरोक्त प्रावधान यदि अनिवार्य नहीं है, बल्कि निर्देशात्मक है, इसलिए इसे इस न्यायालय द्वारा उत्तर दिया जाना आवश्यक है, क्योंकि कार्यालय ने नोट दिया है कि अपील 90 दिनों की अवधि के बाद दायर की गई है, इस प्रकार, यह मुद्दा विचारणीय है कि अधिनियम 2008 की धारा 21(5) में निहित प्रावधान अनिवार्य है या निर्देशात्मक।

20. इस न्यायालय को उपरोक्त मुद्दे का उत्तर देने के लिए अधिनियम 2008 की धारा 21(5) के प्रावधान का संदर्भ लेना आवश्यक है, जो इस प्रकार है:

> *"(5) इस धारा के तहत प्रत्येक अपील उस निर्णय, सजा या आदेश की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर दायर की जाएगी जिसके खिलाफ अपील की जा रही है:*
>
> *यहां तक कि उच्च न्यायालय उक्त तीस दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद अपील को स्वीकार कर सकता है यदि वह संतुष्ट हो कि याचिकाकर्ता ने तीस दिनों की अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था:*
>
> *इसके अतिरिक्त, कोई भी अपील नब्बे दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद स्वीकार नहीं की जाएगी।"*

21. कानून स्पष्ट रूप से स्थापित है कि यदि कोई सांविधिक प्रावधान अपने उद्देश्य और इरादे के संदर्भ में उसी के अनुसार विधान करता है ताकि अधिनियम का वास्तविक उद्देश्य प्राप्त किया जा सके, तो इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बालवंत सिंह बनाम जगदीश सिंह, (2010) 8 एससीसी 685 के मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें पैरा 32 में कहा गया है:

> *"32. यह ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी कोई कानून विधायिका द्वारा बनाया जाता है, तो इसका उद्देश्य इसे उचित दृष्टिकोण में लागू करना होता है। यह कानून का एक समान रूप से स्थापित सिद्धांत है कि अधिनियम के प्रावधानों, जिसमें प्रत्येक शब्द शामिल है, को पूर्ण प्रभाव दिया जाना चाहिए, विधायी इरादे को ध्यान में रखते हुए, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि प्रस्तावित उद्देश्य प्राप्त हो। दूसरे शब्दों में, कोई भी प्रावधान ऐसा नहीं माना जा सकता कि उसे निरर्थक रूप से अधिनियमित किया गया है।"*

22. इस न्यायालय ने उपरोक्त कानूनी सिद्धांत के प्रकाश में अब अधिनियम 2008 के निर्माण का मूल उद्देश्य और कारण संदर्भित करने की प्रक्रिया शुरू की है।

23. इस अधिनियम का मूल उद्देश्य यह है कि देश सीमापार से प्रायोजित बड़े पैमाने पर आतंकवाद का शिकार रहा है। आतंकवादी हमलों की अनगिनत घटनाएँ हुई हैं, न केवल उग्रवाद और विद्रोह से प्रभावित क्षेत्रों और चरमपंथ से प्रभावित क्षेत्रों में, बल्कि विभिन्न भागों में आतंकवादी हमलों और बम विस्फोटों के रूप में भी।

24. सरकार ने उचित विचार-विमर्श के बाद ऐसी स्थिति से निपटने के लिए एक कानून बनाने का प्रस्ताव रखा है ताकि राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी की स्थापना के लिए प्रावधान किए जा सकें, जिसमें विशेष अधिनियमों के तहत विशिष्ट मामलों की जांच करने के लिए प्रावधान और विशेष न्यायालयों की स्थापना या अन्य संबंधित मामलों के लिए प्रावधान शामिल हों।

25. इसलिए, राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी विधेयक, 2008 संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

26. विधेयक को संसद के अधिकांश सदस्यों द्वारा सहमति दी गई थी और यह "राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी अधिनियम, 2008" के रूप में कानून का रूप ले चुका है।

27. इसके अलावा, इस अधिनियम को बनाने का उद्देश्य निर्धारित अपराधों की त्वरित जांच और अभियोजन को सुविधाजनक बनाना है, जिसमें उन अपराधों को भी शामिल किया गया है जो भारत के नागरिकों के खिलाफ या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले अपराधों के रूप में भारत के बाहर किए गए हैं, और अधिनियम में निर्धारित अपराधों की सूची में कुछ नए अपराधों को शामिल करना है जो राष्ट्रीय सुरक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। इसलिए, अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करना आवश्यक हो गया है, जिसके लिए राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (संशोधन) अधिनियम, 2019 के माध्यम से कुछ संशोधन किए गए हैं।

28. उपरोक्त अधिनियम पर राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी के गठन द्वारा कार्य किया गया है।

29. अनुसंधान करने के लिए केंद्रीय सरकार को राज्य सरकार के संबंध में निर्धारित अपराध की जांच करने का अधिकार दिया गया है, जैसा कि अधिनियम 2008 के अध्याय-III में किए गए प्रावधान से स्पष्ट होता है।

30. परीक्षण विशेष न्यायालयों द्वारा अध्याय-IV में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाना अनिवार्य है।

31. विशेष न्यायालयों की स्थापना का उद्देश्य बिना किसी बाधा के त्वरित परीक्षण करना है, ताकि अधिनियम 2008 का वास्तविक उद्देश्य और इरादा पूरी तरह से लागू किया जा सके और देश की अखंडता बनाए रखी जा सके।

32. राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी अधिनियम में एक अनुसूची भी शामिल है जैसा कि धारा 2(1)(f) में संदर्भित किया गया है, जिसके द्वारा कुछ अपराध निर्धारित अपराधों के दायरे में लाए गए हैं, जिसे निम्नलिखित रूप से संदर्भित किया गया है:

"2 (1) (च)" "अनुसूची" "से इस अधिनियम की अनुसूची अभिप्रेत है"

33. धारा 2(1)(f) 'अनुसूची' की परिभाषा से संबंधित है, जिसका अर्थ है इस अधिनियम की अनुसूची और सभी निर्धारित अपराध जो धारा 2(1)(जी) के तहत प्रदान किए गए हैं, विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई की जाएगी और राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी द्वारा जांच की जाएगी, जैसा कि धारा 6 में किए गए प्रावधान के अनुसार है, जो केंद्रीय सरकार को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी द्वारा जांच करने का कार्य ले सके। इसके अलावा, केंद्रीय सरकार को अपने आप से जांच लेने का भी अधिकार है, लेकिन उपरोक्त प्रावधान के साथ-साथ, धारा 10 भी है जो राज्य सरकार को निर्धारित अपराधों की जांच करने का अधिकार प्रदान करती है।

34. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी, 2008 के गठन का मुख्य उद्देश्य उन निर्धारित अपराधों से निपटना है जो आरोपों की प्रकृति के संदर्भ में गंभीरता रखते हैं, जिसमें यू.ए.(पी) अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम आदि शामिल हैं।

35. अधिनियम 2008 को एक आत्म-निहित अधिनियम बनाया गया है और इसमें अपील के फोरम के लिए भी प्रावधान किया गया है जैसा कि इसकी धारा 21 में है। उक्त प्रावधान एक गैर-रोकने वाली धारा के साथ शुरू होता है कि कोड में निहित किसी भी बात के बावजूद, विशेष न्यायालय के किसी भी निर्णय, सजा या आदेश (जो अंतर्वर्ती आदेश नहीं हो) से उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, दोनों तथ्यों और कानून पर।

36. धारा 21 का उप-धारा (2) यह प्रदान करती है कि उप-धारा (1) के तहत प्रत्येक अपील उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनी जाएगी और इसे संभवतः अपील के प्रवेश की तिथि से तीन महीने के भीतर निस्तारित किया जाएगा।

37. धारा 21 का उप-धारा (3) यह प्रदान करती है कि किसी विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, सजा या आदेश (जिसमें अंतर्वर्ती आदेश शामिल हैं) से किसी भी न्यायालय में कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं होगा।

38. धारा 21 का उप-धारा (4) यह प्रदान करती है कि विशेष न्यायालय द्वारा जमानत देने या अस्वीकृत करने वाले आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

39. लेकिन ऐसी अपील दायर करने के लिए एक शर्त रखी गई है कि इसे या तो धारा 21(1) या धारा 21(4) के तहत निर्णय, सजा या आदेश की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर दायर किया जाना चाहिए।

40. धारा 21(5) में दो उपबंध शामिल हैं;

    "पहला उपबंध उच्च न्यायालय को यह अधिकार प्रदान करता है कि उच्च न्यायालय उक्त तीस दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद अपील को स्वीकार कर सकता है यदि वह संतुष्ट हो कि याचिकाकर्ता के पास तीस दिनों की अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था।"

    दूसरा उपबंध बहुत स्पष्ट है, जो यह प्रदान करता है "कि नब्बे दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी।"

41. अधिनियम 2008 के निर्माण का मुख्य उद्देश्य निर्धारित अपराधों की सुनवाई के लिए एक फोरम और अपील के लिए एक फोरम प्रदान करना है, जैसा कि अधिनियम 2008 की धारा 2(1)(जी) में संदर्भित किया गया है।

42. विशेष न्यायालय का गठन करने का मुख्य उद्देश्य न्याय की प्रक्रिया में तेजी लाना है और इसके अलावा, धारा 21(1), 21(3) और 21(4) में प्रावधान किए गए हैं, जिसके द्वारा फोरम प्रदान किया गया है।

43. फोरम को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि इसे उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा सुना जाएगा, जिसका अर्थ निहित रूप से यह है कि निर्धारित अपराध गंभीर प्रकृति के होते हैं और अधिनियम एक उपाय है, इसलिए इसे उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा सुना जाना चाहिए।

44. इसके अलावा, कुछ निर्धारित अपराधों में, उदाहरण के लिए, यू.ए.(पी) अधिनियम, 1967 में, पूर्व-गिरफ्तारी जमानत का कोई प्रावधान नहीं है, जो यू.ए.(पी) अधिनियम, 1967 की धारा 43(डी)(5) के तहत लगाए गए विशेष प्रतिबंध के कारण है। इसलिए, विधायिका ने कुछ निर्धारित अपराधों को पूर्व-

गिरफ्तारी जमानत के विशेषाधिकार से बाहर रखा है और इस प्रकार, विशेष न्यायालय द्वारा पारित आदेश की उचितता पर विचार करने के लिए जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 से संबंधित है उस व्यक्ति के संबंध में जो हिरासत में लिया गया है, लेकिन ऐसा आरोपी व्यक्ति पूर्व-गिरफ्तारी जमानत दायर करने की स्थिति में नहीं हो सकता यदि उसे हिरासत में पूछताछ के लिए लिया गया हो और जब नियमित जमानत की प्रार्थना अस्वीकृत कर दी गई हो, तो इसे डिवीजन बेंच द्वारा सुना जाना चाहिए।

45. ऐसी व्यवस्था बनाते समय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्थापित सिद्धांत को भी ध्यान में रखा गया है। लेकिन कानून यह भी निर्धारित करता है कि यदि किसी व्यक्ति ने ऐसे अपराध किए हैं जो निर्धारित अपराधों के दायरे में आते हैं, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अपराध करने पर हावी नहीं होने दिया जाएगा ताकि देश में संतुलन और कानून के शासन को बनाए रखा जा सके।

46. निस्संदेह, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 एक मौलिक अधिकार है जिसे एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसी सुरक्षा प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करती है और यदि किसी व्यक्ति को निर्धारित अपराधों जैसे गंभीर अपराधों का दोषी या जाता है, तो कानून के शासन को बनाए रखने का प्रश्न अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता के अधिकार पर हावी कहा जाएगा।

47. धारा 21(5) के प्रावधान को निर्देशात्मक और अनिवार्य न घोषित करने का प्रश्न यहाँ मूल प्रश्न है।

48. यह विवादित नहीं है कि धारा 21(5) में दो प्रावधान शामिल हैं, पहला उपबंध जो इस प्रकार है:

> "यहां तक कि उच्च न्यायालय उक्त तीस दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद अपील को स्वीकार कर सकता है यदि वह संतुष्ट हो कि याचिकाकर्ता ने तीस दिनों की अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था।"

49. पहले उपबंध में अंग्रेजी के 'मे' शब्द है, जिसे याचिकाकर्ता के अनुसार निर्देशात्मक और न कि अनिवार्य माना जाता है, जिसके अनुसार अपील 30 दिनों की अवधि के भीतर दायर की जानी चाहिए और यदि पर्याप्त कारण दिखाया जाता है, तो अपीलीय न्यायालय को देरी को माफ करने का अधिकार होगा।

50. दूसरा उपबंध भी है जो इस प्रकार है:

"यहां तक कि नब्बे दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी।"

51. दूसरा उपबंध यह निर्धारित करता है कि अपीलीय न्यायालय नब्बे दिनों की अवधि से अधिक कोई अपील स्वीकार नहीं करेगा।

52. मामला अलग होता यदि धारा 21(5) में केवल एक उपबंध होता, अर्थात् पहला उपबंध, लेकिन इसमें दूसरा उपबंध जोड़ा गया है, जिसमें 90 दिनों की अवधि के बाद अपील स्वीकार न करने का विशेष प्रावधान अंग्रेजी के 'शैल' शब्द का उपयोग करके किया गया है।

53. उपरोक्त दो उपबंधों को एक साथ पढ़ने पर, इस न्यायालय के विचार के अनुसार, धारा 21(5), जो अपील दायर करने की समय सीमा 90 दिनों की अवधि में प्रदान करती है, अनिवार्य मानी जाएगी।

54. इसके अलावा, उक्त प्रावधान को अनिवार्य मानने का निष्कर्ष अधिनियम के उद्देश्य और इरादे को प्राप्त करने के लिए है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पाटिल ऑटोमेशन (पी) लिमिटेड बनाम रेखेजा इंजीनियर्स (पी) लिमिटेड, (2022) 10 एससीसी 1 के मामले में दिए गए निर्णय में कहा गया है, जिसमें अंग्रेजी के 'मे' और 'शैल' के अर्थ पर चर्चा की गई है, अर्थात् किन परिस्थितियों में अंग्रेजी के 'मे'' शब्द निर्देशात्मक और अनिवार्य होगा। उपरोक्त निर्णय के प्रासंगिक पैरा यहाँ उद्धृत किए जा रहे हैं:

"32. पांच न्यायाधीशों की पीठ ने राज्य उत्तर प्रदेश बनाम बाबू राम उपाध्याय [राज्य उत्तर प्रदेश बनाम बाबू राम उपाध्याय, एआइआर 1961 एससी 751] में यह प्रश्न विचार किया कि क्या पुलिस अधिनियम की धारा 7 के तहत बनाए गए पुलिस नियमों का पैरा 486 अनिवार्य था या नहीं। मूल रूप से, उक्त पैरा ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत मजिस्ट्रियल जांच पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया, जब पुलिस अधिकारी के खिलाफ आरोपित अपराध केवल पुलिस अधिनियम की धारा 7 के तहत था।

33. बाबू राम उपाध्याय [राज्य उत्तर प्रदेश बनाम बाबू राम उपाध्याय, एआइआर 1961 एससी 751] में बहुमत के लिए लिखित राय में, न्यायमूर्ति के. सुब्बा राव ने उस समय के लिए प्रासंगिक नियमों को संक्षेप में प्रस्तुत किया जब अधिनियम अंग्रेजी के 'शैल' शब्द का उपयोग करता है: (AIR पृष्ठ 765, पैरा 29)

"29. व्याख्या के प्रासंगिक नियमों को संक्षेप में इस प्रकार stated किया जा सकता है: जब कोई अधिनियम 'shall' शब्द का उपयोग करता है, तो प्राथमिक दृष्टि में यह अनिवार्य होता

है, लेकिन न्यायालय विधायिका की वास्तविक मंशा को जानने के लिए अधिनियम के पूरे दायरे पर ध्यान देकर पता लगा सकता है। विधायिका की वास्तविक मंशा को जानने के लिए न्यायालय निम्नलिखित बातों पर विचार कर सकता है: अधिनियम की प्रकृति और डिज़ाइन, और इसे एक निश्चित तरीके से या दूसरे तरीके से व्याख्यायित करने के परिणाम, अन्य प्रावधानों का प्रभाव जिसके द्वारा संबंधित प्रावधानों का पालन करने की आवश्यकता से बचा जा सकता है, यह परिस्थिति कि अधिनियम प्रावधानों के अनुपालन की स्थिति के लिए प्रावधान करता है, यह तथ्य कि प्रावधानों का अनुपालन न करने पर कुछ दंड लगाया जाता है या नहीं, इसके परिणामस्वरूप गंभीर या तुच्छ परिणाम, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या विधायी उद्देश्य को विफल किया जाएगा या आगे बढ़ाया जाएगा।"

55. उपरोक्त निर्णय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह सिद्धांत स्थापित किया है कि अधिनियम को इसके उद्देश्य और इरादे के आधार पर अनिवार्य माना जाएगा।

56. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विदर्भा इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड बनाम एक्सिस बैंक लिमिटेड, (2022) 8 एससीसी 352 में देखा कि सामान्यतः 'मे' शब्द निर्देशात्मक होता है। 'मे एडमिट' का अर्थ है स्वीकार करने की विवेकाधीनता। इसके विपरीत, 'शैल' शब्द का उपयोग अनिवार्य आवश्यकता को दर्शाता है, जिसमें पैरा-64 में कहा गया है:

"64. सामान्यतः 'मे' शब्द निर्देशात्मक होता है। 'मे एडमिट' का अर्थ है स्वीकार करने की विवेकाधीनता। इसके विपरीत, 'शैल ' शब्द का उपयोग अनिवार्य आवश्यकता को दर्शाता है। 'shall' शब्द का उपयोग यह पूर्वधारणा उत्पन्न करता है कि प्रावधान अनिवार्य है। हालाँकि, यह स्पष्ट रूप से स्थापित है कि प्रावधान के अनिवार्य होने के बारे में प्राथमिक दृष्टि की धारणा अन्य विचारों जैसे अधिनियम के दायरे और व्याख्या से उत्पन्न होने वाले परिणामों द्वारा खंडित की जा सकती है।"

57. यह भी एक स्थापित व्याख्या का सिद्धांत है कि यदि परिस्थितियाँ मांग करती हैं तो 'may' शब्द को 'shall' के रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है। इस संबंध में राज्य कर अधिकारी बनाम रेनबो पेपर्स लिमिटेड मामले से संदर्भ लिया जा सकता है, जो 2022 लाइव लॉ (SC) 743 में रिपोर्ट किया गया है।

58. यहाँ, अधिनियम का उद्देश्य एक निवारक प्रभाव डालना और उन अवैध कार्य करने वालों को संदेश देना है जिन्होंने निर्धारित अपराधों के दायरे में आने वाले अपराध किए हैं, जो देश की अखंडता से संबंधित हैं। इसलिए, अधिनियम 2008 की धारा 21(5) के तहत प्रावधान किया गया है और दूसरे

उपबंध के अनुसार यह निर्धारित किया गया है कि नब्बे दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी।

59. प्रश्न यह है कि यदि अधिनियम 2008 की धारा 21(5) का दूसरा उपबंध निर्देशात्मक कहा जाएगा, तो क्या अधिनियम का वास्तविक उद्देश्य और इरादा प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में, यदि अपील को 90 दिनों की अवधि के बाद भी दायर करने की अनुमति दी जाती है, तो यह एक वर्ष/दो वर्ष/तीन वर्ष/पांच वर्ष या किसी भी समय के बाद भी हो सकता है।

60. धारा 21(5) के तहत देरी को माफ करने का सिद्धांत पर्याप्त कारण पर आधारित है, तो ऐसी परिस्थितियों में, यदि किसी व्यक्ति को निर्धारित अपराध के तहत दोषी ठहराया गया है, तो वह पर्याप्त कारण का औचित्य देते हुए अत्यधिक देरी के बाद भी अपील दायर करेगा। तब उस उद्देश्य और इरादे का क्या होगा जिसके लिए अधिनियम बनाया गया है, अर्थात् समाज को यह संदेश देना कि यदि निर्धारित अपराध किया जाएगा तो संबंधित व्यक्ति को वहां उल्लिखित दंड के साथ दंडित किया जाएगा।

61. इसे एक अन्य दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है कि यदि किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है और यदि उसे विशेष न्यायालय द्वारा पारित आदेश में स्पष्ट अवैधता मिलती है, तो विधायिका ने निर्धारित अवधि के भीतर अपील दायर करने का आदेश दिया है ताकि इसे अपीलीय न्यायालय द्वारा आंका जा सके और यदि विशेष न्यायालय द्वारा की गई अवैधता को सुधारने के लिए आवश्यक हो, तो अधिनियम के अनुच्छेद 21 के वास्तविक उद्देश्य और इरादे को प्राप्त किया जा सके।

62. यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि यदि कोई व्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार का दावा करता है और उसने अधिकतम 90 दिनों की अवधि में अपील नहीं दायर की, तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को अनुच्छेद 21 की भावना का उल्लंघन करने का दावा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसका कारण यह है कि जब अधिनियम स्वयं इस तथ्य पर विचार करता है कि अपील 90 दिनों की अवधि के भीतर दायर की जानी चाहिए ताकि मुद्दा अपीलीय न्यायालय द्वारा तय किया जा सके, तो इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 पर विचार माना जाएगा। और यदि अपील 90 दिनों की अवधि के बाद दायर की जाती है, तो उस व्यक्ति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करने का दावा करने की अनुमति कैसे दी जा सकती है।

63. इसके अलावा, भारत के संविधान के भाग-III में मौलिक अधिकारों को प्रदान करते हुए, जिसमें अनुच्छेद 21 भी शामिल है, यदि इसे कोई व्यक्ति या कोई अन्य मौलिक अधिकार का उपयोग करता है, तो उस व्यक्ति को सांविधिक उपायों के प्रति सतर्क रहना चाहिए।

64. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अधिनियम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक ओर और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के सिद्धांत को सुरक्षित करने के लिए, यह कहा जाएगा कि यह तभी पूरा होगा जब अधिनियम को संपूर्णता में पढ़ा जाएगा और इसका इरादा प्राप्त किया जाएगा, यदि सांविधिक प्रावधान का उचित पालन किया जाए।

65. अपील दायर करने के लिए 90 दिनों की अवधि इस उद्देश्य के लिए प्रदान की गई है कि पीड़ित को अपील करने का अवसर दिया जा सके ताकि उसे जल्दी से जल्दी उस आदेश या निर्णय या सजा में मौजूद विकृति पर ध्यान देने का अवसर मिल सके या जमानत की प्रार्थना को अस्वीकृत करने वाले आदेश में।

66. केवल उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर जो अपीलीय न्यायालय द्वारा विचार किया जाएगा, कहा जाएगा कि यह अधिनियम के उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में है ताकि समाज को एक संदेश दिया जा सके यदि निर्णय या सजा या जमानत की प्रार्थना अस्वीकृत करने वाला आदेश अपीलीय न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया है।

67. दूसरी ओर, यदि अपीलीय न्यायालय विशेष न्यायालय द्वारा पारित आदेश में दोष पाता है, तो वही आदेश उलट दिया जाएगा और इस मामले में, संबंधित व्यक्ति जिसे अनुचित आदेश से नकारात्मक रूप से प्रभावित किया गया था, उसे न्यायिक हिरासत में आने की अनुमति दी जाएगी और इस प्रकार अनुच्छेद 21 का सिद्धांत संरक्षित रहेगा।

68. यहाँ, अपील दायर करने के लिए अधिकतम 90 दिनों की अवधि प्रदान की गई है और इस प्रकार, यदि संबंधित आरोपी व्यक्ति निर्धारित अपराध से संबंधित मामले में आरोपित है, तो उसे सांविधिक प्रावधानों के तहत निर्धारित अवधि के भीतर अपील करने की आवश्यकता है ताकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उद्देश्य प्राप्त किया जा सके।

69. इसके अलावा, कानून की स्थापित स्थिति यह है कि अधिनियम में निहित प्रावधान को संपूर्णता में पढ़ा जाना चाहिए और अन्य प्रावधानों को छोड़कर केवल विशिष्ट प्रावधान को नहीं देखा जाना चाहिए जैसा कि उक्त अधिनियम में शामिल हैं।

70. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल राज्य बनाम भारत संघ मामले में [एआइआर 1963 एससी 1241] पृष्ठ 1245 पर अधिनियम को संपूर्ण रूप से व्याख्यायित करने के महत्व पर जोर दिया है, प्रासंगिक पैरा यहाँ संदर्भित किया जा रहा है:

"न्यायालय को विधायिका की मंशा का पता लगाना चाहिए, न केवल उन धाराओं को ध्यान में रखते हुए जिन्हें व्याख्यायित किया जाना है, बल्कि संपूर्ण अधिनियम को भी; इसे उस धारा की तुलना अन्य कानून के भागों से करनी चाहिए, और उस संदर्भ को देखना चाहिए जिसमें व्याख्या की जाने वाली धारा आती है।"

71. इसी प्रकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एन.के. जैन बनाम सी.के. शाह मामले में (1991) 2 एससीसी 495 में निर्णय दिया है कि किसी अधिनियम के प्रावधान की व्याख्या करते समय विधायी उद्देश्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए और अधिनियम को संपूर्णता में पढ़ा जाना चाहिए। उपरोक्त निर्णय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ने पैरा 13 में कहा है:

"विधायी उद्देश्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए और अधिनियम को संपूर्णता में पढ़ा जाना चाहिए। हमारे विचार में, अधिनियम के अंतर्निहित उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए और धारा 14 और 17 को पूरी तरह से पढ़ने पर, यह स्पष्ट हो जाता है कि दी गई छूट का रद्द होना धारा 14(2-ए) के अर्थ में दंड नहीं है।"

72. यह न्यायालय, अधिनियम के वास्तविक उद्देश्य और इरादे को ध्यान में रखते हुए और धारा 21(5) के दोनों उपबंधों को एक साथ पढ़ते हुए, इस विचार का है कि अपील दायर करने का उपरोक्त प्रावधान अधिकतम 90 दिनों की अवधि के भीतर अनिवार्य है।

73. इस न्यायालय ने इस मुद्दे पर विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों पर विचार किया है, अर्थात् केरल उच्च न्यायालय द्वारा नासिर अहमद बनाम राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी मामले में, जो 2015 एससीसी ऑनलाइन केरल 39625 में रिपोर्ट किया गया है, जिसमें अपील का मुद्दा यह था कि अधिनियम 2008 की धारा 21 के तहत अपील निर्णय की तिथि से 90 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद दायर की जा सकती है या नहीं और क्या उच्च न्यायालय धारा 5 के तहत अपील दायर करने में देरी को माफ कर सकता है।

74. केरल उच्च न्यायालय ने उक्त मुद्दे का उत्तर देते हुए अधिनियम के वास्तविक उद्देश्य को ध्यान में रखा और पैरा-22 से स्पष्ट होता है कि उसने निष्कर्ष निकाला कि धारा 5 का समय सीमा अधिनियम लागू नहीं होगा और धारा 21(5) के तहत निर्धारित समय सीमा 90 दिनों की अवधि अनिवार्य है। संदर्भ के लिए, उक्त निर्णय का पैरा-22 इस प्रकार है:

"22. परक्राम्य लिखत अधिनियम एक ऐसा अधिनियम है जो राष्ट्रीय स्तर पर एक अन्वेषण एजेंसी का गठन करता है ताकि भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता, राज्य की सुरक्षा,

विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों और अंतरराष्ट्रीय संधियों, समझौतों, सम्मेलनों और संयुक्त राष्ट्र, इसकी एजेंसियों और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रस्तावों के कार्यान्वयन के लिए अधिनियमित अपराधों की जांच और अभियोजन किया जा सके, और इससे संबंधित या उसके अनुषंगी मामलों की जांच की जा सके। परक्राम्य लिखत का पर्यवेक्षण केंद्रीय सरकार के पास होगा, जैसा कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 4 में प्रदान किया गया है। धारा 6 निर्धारित अपराधों की जांच के लिए प्रावधान करती है। धारा 7 में कहा गया है कि परक्राम्य लिखत राज्य सरकार से जांच में सहयोग करने का अनुरोध कर सकती है। धारा 9 यह अनिवार्य करती है कि राज्य सरकार निर्धारित अपराधों की जांच के लिए एजेंसी को सभी सहायता और सहयोग प्रदान करेगी। निर्धारित अपराधों के परीक्षण के लिए धारा 11 के तहत विशेष न्यायालयों का गठन किया गया है। परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 15 में सार्वजनिक अभियोजकों और अतिरिक्त सार्वजनिक अभियोजकों की नियुक्ति का प्रावधान है। धारा 16 विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियों के लिए प्रावधान करती है। परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 19 कहती है कि अधिनियम के तहत किसी भी अपराध का परीक्षण विशेष न्यायालय द्वारा दिन-प्रतिदिन आधार पर सभी कार्य दिवसों पर किया जाएगा और यह किसी अन्य न्यायालय (जो विशेष न्यायालय नहीं है) में आरोपी के खिलाफ किसी अन्य मामले के परीक्षण पर प्राथमिकता रखेगा और इसे ऐसे अन्य मामले के परीक्षण से पहले समाप्त किया जाएगा, और इस प्रकार यदि आवश्यक हो तो ऐसे अन्य मामले का परीक्षण स्थगित रहेगा। धारा 21 का उप-धारा (2) कहता है कि उप-धारा (1) के तहत प्रत्येक अपील उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनी जाएगी और इसे संभवतः अपील के प्रवेश की तिथि से तीन महीने के भीतर निस्तारित किया जाएगा। परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 21 के उप-धारा (5) के उपबंधों का दायरा अधिनियम में अन्य प्रावधानों की दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए। उप-धारा (5) की धारा 21 में दी गई समय सीमा तीस दिन है। उप-धारा (5) का पहला उपबंध उच्च न्यायालय को यह अधिकार देता है कि वह तीस दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद अपील को स्वीकार कर सकता है, यदि वह संतुष्ट हो कि याचिकाकर्ता ने तीस दिनों की अवधि में अपील न करने का पर्याप्त कारण बताया है। दूसरा उपबंध यह प्रदान करता है कि नब्बे दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी। उप-धारा (5) का पहला उपबंध स्वयं अपील दायर करने में देरी को माफ करने से संबंधित है और आदेश की तिथि से नब्बे दिनों तक (छह दशक तक) देरी को उच्च न्यायालय द्वारा माफ किया जा सकता है। यह प्रतिबंध लगाते हुए कि नब्बे दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद कोई अपील स्वीकार

नहीं की जाएगी, धारा 5 का समय सीमा अधिनियम स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है। उच्च न्यायालय को अपील दायर करने में देरी को माफ करने का अधिकार है। लेकिन यह अधिकार उप-धारा (5) के पहले उपबंध के तहत सीमित है। दूसरे उपबंध में एक और प्रतिबंध स्पष्ट रूप से यह संकेत देता है कि उच्च न्यायालय धारा 5 के तहत देरी को माफ करने का अधिकार नहीं रखता। इस हद तक, यह समय सीमा अधिनियम की धारा 5 को स्पष्ट रूप से बाहर रखने के बराबर है जैसा कि समय सीमा अधिनियम की धारा 29(2) में समाहित किया गया है। उपरोक्त कारणों से, हम इस विचार पर हैं कि देरी को माफ करने हेतु आवेदन स्वीकार्य नहीं है। इसलिए, देरी को माफ करने हेतु आवेदन तथा आपराधिक अपील दोनों को अस्वीकार किया जाता है।"

75. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी शेख रहमतुल्ला एवं अन्य बनाम राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी के मामले में इसी मुद्दे पर विचार किया है, जो 2023 एससीसी ऑनलाइन कलकत्ता 493 में रिपोर्ट किया गया है, जहाँ यह मुद्दा भी उठाया गया था कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 2008 की धारा 21 के तहत 90 दिनों के बाद अपील दायर की जा सकती है और इसे समय सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत माफ किया जा सकता है।

76. हम, उक्त निर्णय को पढ़ने के बाद यह पाए हैं कि अधिनियम 2008 को विशेष कानून माना गया है जो उन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है जो निर्धारित अपराधों से संबंधित हैं, जिन्हें विशेष न्यायालयों द्वारा अधिनियम 2008 के तहत मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा, यह स्थापित कानूनी स्थिति का संदर्भ देते हुए कहा गया है कि अधिनियम विधायिका का आदेश है और किसी अधिनियम की व्याख्या या व्याख्या करने का पारंपरिक तरीका विधायिका की मंशा को जानना है। विधायिका की मंशा को संपूर्ण अधिनियम को पढ़कर पाया जाना चाहिए। जहाँ अधिनियम के शब्द स्पष्ट, सरल या अस्पष्ट हैं, वहाँ न्यायालयों को उस अर्थ को लागू करने के लिए बाध्य किया जाता है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। संदर्भ के लिए, इस निर्णय के पैरा-67 और 69 को यहाँ उद्धृत किया जा रहा है:

> *"67. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, अधिनियम 2008 एक विशेष कानून है जो उन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है जो निर्धारित अपराधों से संबंधित हैं जिन्हें विशेष न्यायालयों द्वारा अधिनियम 2008 के तहत निर्णय लेने का कार्य सौंपा गया है।*
>
> *69. यह सामान्य कानून है कि अधिनियम विधायिका का आदेश है और किसी अधिनियम की व्याख्या या व्याख्या करने का पारंपरिक तरीका विधायिका की मंशा को जानना है। विधायिका की मंशा को संपूर्ण अधिनियम को पढ़कर पाया जाना चाहिए। जहाँ अधिनियम*

के शब्द स्पष्ट, सरल या अस्पष्ट हैं, वहाँ न्यायालयों को उस अर्थ को लागू करने के लिए बाध्य किया जाता है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। यह गलत और खतरनाक है कि किसी अन्य शब्दों को अधिनियम के शब्दों के स्थान पर रखा जाए। व्याख्या के नियम न्यायालयों को शब्द जोड़ने की अनुमति नहीं देते जब तक कि धारा जैसा कि वह खड़ी है निरर्थक या संदिग्ध अर्थ की न हो।"

77. मुंबई उच्च न्यायालय ने भी इसी मुद्दे पर विचार किया है कि क्या अपीलीय न्यायालय के पास अधिनियम 2008 की धारा 21(5) के दूसरे उपबंध के अनुसार 90 दिनों की अवधि के बाद दायर की गई अपील को स्वीकार करने का अधिकार है।

78. उक्त मुद्दे का उत्तर देते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की वास्तविक भावना को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकाला गया कि धारा 21(5) को अनिवार्य नहीं माना जा सकता, अन्यथा इससे न्याय का मजाक उड़ाने की स्थिति उत्पन्न होगी। यह निष्कर्ष इस आधार पर निकाला गया कि यदि धारा 21(5) का प्रावधान अनिवार्य माना जाएगा, तो इससे न्याय का मजाक उड़ाना होगा।

79. दिल्ली ने भी वही दृष्टिकोण अपनाया है जो मुंबई उच्च न्यायालय ने फारहान शेख बनाम राज्य (राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी) के मामले में लिया था, जो 2019 एससीसी ऑनलाइन दिल्ली 9158 में रिपोर्ट किया गया है।

80. इस समय यह लाभदायक होगा कि हम इस स्थापित कानूनी अर्थ पर चर्चा करें कि विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का बाध्यकारी प्रभाव नहीं होता, बल्कि यह प्रेरक होता है। यह भी स्थापित स्थिति है कि यदि कोई उच्च न्यायालय विभिन्न उच्च न्यायालयों या किसी अन्य उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण से सहमत नहीं होता है, तो संबंधित उच्च न्यायालय को यह बताना आवश्यक है कि किसी अन्य उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को प्रेरक मूल्य क्यों नहीं माना जा रहा है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदीप जे. मेहता बनाम आयकर आयुक्त, अहमदाबाद, (2008) 14 एससीसी 283 के मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें पैरा-23 में कहा गया है:-

"23. हालाँकि, उपरोक्त निर्णयों का उल्लेख उच्च न्यायालय में बार में किया गया था, जिन्हें उच्च न्यायालय की पीठ के माननीय न्यायाधीशों ने ध्यान में रखा, लेकिन न तो उन्होंने अपनी सहमति या असहमति दर्ज की और न ही उन्होंने राजस्व के पक्ष में संदर्भित दो प्रश्नों का उत्तर दिया। न्यायिक शिष्टाचार, उचितता और अनुशासन की आवश्यकता थी कि

उच्च न्यायालय, विशेष रूप से यदि इसका विपरीत दृष्टिकोण या असहमति हो, तो विभिन्न उच्च न्यायालयों के उपरोक्त निर्णयों पर चर्चा करता और अपने विपरीत दृष्टिकोण के लिए अपने कारण दर्ज करता। हम यह तथ्य स्पष्ट रूप से देखते हैं कि एक उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय अन्य उच्च न्यायालयों पर बाध्यकारी नहीं होते, लेकिन फिर भी, उनके पास प्रेरक मूल्य होता है। एक अन्य उच्च न्यायालय को अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से असहमत होने का अधिकार है, लेकिन सभी निष्पक्षता में, उच्च न्यायालय को अपनी असहमति को कारणों के साथ दर्ज करना चाहिए। अन्य उच्च न्यायालयों के निर्णय, हालांकि बाध्यकारी नहीं हैं, फिर भी उनके पास प्रेरक मूल्य होता है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए और अपनी स्वयं की कारणों के साथ असहमत होना चाहिए।"

81. हम अब विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों की जांच करने जा रहे हैं, अर्थात् मुंबई उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय, यह देखने के लिए कि इनमें से कौन सा निर्णय यहाँ उठाए गए मुद्दे के लिए प्रेरक मूल्य रखता है।

82. हम, केरल उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों को पढ़ने के बाद यह पाए हैं कि मुंबई उच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय ने विचार किया कि यदि अपील को 90 दिनों की अवधि के बाद दायर करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो इससे न्याय का मजाक उड़ाने की स्थिति उत्पन्न होगी और अंततः यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के खिलाफ होगा।

83. लेकिन, हम इस दृष्टिकोण से सम्मानपूर्वक असहमत हैं क्योंकि यदि सांविधिक अनिवार्यता ने अधिकतम 90 दिनों की अवधि के भीतर अपील दायर करने का प्रावधान किया है, तो अपील को अधिकतम 90 दिनों की अवधि के भीतर दायर किया जाना चाहिए। और इन परिस्थितियों में, यदि कोई व्यक्ति जांच के दौरान हिरासत में है या दोषसिद्धि के निर्णय के बाद हिरासत में है, तो अपील को अधिकतम 90 दिनों की अवधि में दायर करना आवश्यक होगा जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के वास्तविक उद्देश्य और इरादे को प्राप्त करने में सहायक होगा। इसका कारण यह है कि यदि दोषसिद्धि के निर्णय में कोई विकृति है या कोई आदेश जो संबंधित व्यक्ति को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है, तो इसे तुरंत विशेष अवधि के भीतर दायर किया जाना चाहिए।

84. यदि समय सीमा अधिनियम की धारा 5, जिसे मुंबई उच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा लागू माना गया है, को प्रभावी होने की अनुमति दी जाती है, तो अपील को अत्यधिक देरी के बाद भी दायर किया जा सकता है, यदि देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण दिखाए

जाते हैं, जो समय सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के प्रावधानों का उपयोग करते हुए किया जाएगा, जो अंततः भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के मूल सिद्धांत का उल्लंघन करेगा।

85. हमारे विचार में, केरल उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय निम्नलिखित कारणों से प्रेरक मूल्य रखेगा:

(i) यदि धारा 21(5) के तहत देरी को माफ करने का सिद्धांत पर्याप्त कारण पर आधारित है, तो ऐसी परिस्थितियों में, यदि किसी व्यक्ति को निर्धारित अपराध के तहत दोषी ठहराया गया है, तो वह अत्यधिक देरी के बाद भी अपील दायर करेगा और देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण का औचित्य देगा। तब उस उद्देश्य और इरादे का क्या होगा जिसके लिए अधिनियम बनाया गया है।

(ii) इसके अलावा, जब कोई व्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार का दावा करता है और यदि उसने अधिकतम 90 दिनों की अवधि में अपील नहीं दायर की, तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को अनुच्छेद 21 की भावना का उल्लंघन करने का दावा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसका कारण यह है कि जब अधिनियम स्वयं इस तथ्य पर विचार करता है कि अपील को अधिकतम 90 दिनों की अवधि में दायर किया जाना चाहिए ताकि मुद्दा अपीलीय न्यायालय द्वारा तय किया जा सके। यदि अपील 90 दिनों की अवधि के बाद दायर की जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करने का दावा करने की अनुमति कैसे दी जा सकती है।

(iii) इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अधिनियम के उद्देश्य को प्राप्त करने और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के सिद्धांत को सुरक्षित रखने के लिए यह कहा जाएगा कि यह तभी पूरा होगा जब अधिनियम को संपूर्णता में पढ़ा जाएगा और इसका इरादा प्राप्त किया जाएगा, यदि सांविधिक प्रावधान का उचित पालन किया जाए।

(iv) अपील दायर करने के लिए प्रदान की गई 90 दिनों की अवधि पीड़ित को अपील करने का अवसर प्रदान करने के लिए है ताकि जल्दी से जल्दी उस आदेश या निर्णय में मौजूद विकृति पर ध्यान दिया जा सके या जमानत की प्रार्थना को अस्वीकृत करने वाले आदेश में।

86. इसलिए, यह न्यायालय इस विचार पर है कि अधिनियम 2008 की धारा 21(5) में निहित प्रावधान जो अधिकतम 90 दिनों की अवधि में अपील दायर करने का अनिवार्य करता है, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का वास्तविक उद्देश्य प्राप्त करेगा।

87. इस न्यायालय ने उपरोक्त चर्चा के आधार पर, केरल उच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की है।

88. इसके अतिरिक्त, मुंबई उच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के अनुसार, इस न्यायालय के विचार में और संबंधित उच्च न्यायालयों के प्रति सभी उचित सम्मान के साथ, यह कहा गया है कि उपरोक्त निर्णयों को प्रेरक स्वरुप का नहीं माना जा रहा है, क्योंकि जिन कारणों पर केरल उच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों को प्रेरक स्वरुप का माना गया है, वे यहाँ संदर्भित किए गए हैं।

89. यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि सुनवाई के दौरान बार में यह बताया गया था कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थगित रखा गया है।

90. हम इसकी जांच करने पर पाए हैं कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) डायरी संख्या 41439/2019 में 02-12-2019 को पारित आदेश द्वारा स्थगित रखा है।

91. इस प्रकार, और उपरोक्त चर्चा के आधार पर, यह न्यायालय इस विचार पर है कि कार्यालय नोट जो वर्तमान अपील की स्वीकार्यता पर आपत्ति उठाता है, यह देखते हुए कि अपील अधिकतम सांविधिक अवधि 90 दिनों की समाप्ति के बाद दायर की गई है, इसे यहाँ बनाए रखा जाता है।

92. परिणामस्वरूप, वर्तमान अपील असफल होती है और इसे स्वीकार्यता के आधार पर खारिज किया जाता है।

(न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद)

(न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव)

यह अनुवाद संजय नारायण, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|